

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132]

दिल्ली, सोमवार, जुलाई 8, 2019/आषाढ़ 17, 1941

[रा.रा.क्षे.दि. सं. 91

No. 132]

DELHI, MONDAY, JULY 8, 2019/ASHADHA 17, 1941

[N.C.T.D. No. 91

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 5 जुलाई, 2019

फा. सं. 28(18)/2017-18/डीएससीएसटी/प्ला./खण्ड-I/8253-65.—दिनांक 20 अप्रैल 1993 की अधिसूचना सं० 28(93)/91-92/एससीएसटी/पीएण्डएस/109 की खण्ड 14 के अनुसरण में जिसके अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप राज्यपाल एवं मंत्रीमण्डल निर्णय सं० 2600 दिनांक 17.07.2018 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष एवं अंशकालिक सदस्यों को देय वेतन एवं भत्तों को दिनांक 17.07.2018 से निम्नानुसार विनियमित करती है।

“अध्यक्ष का समेकित वेतन बिना भत्ते के रु० 2,00,000/- (दो लाख मात्र) प्रतिमाह होगा तथा इसके अतिरिक्त अध्यक्ष कार एवं मकान (या नियमानुसार यथा-लागू मकान किराया भत्ता) का पात्र होगा। अंशकालिक सदस्य बिना भत्ते के रु० 1,00,000/- (एक लाख मात्र) समेकित की मासिक राशि के पात्र होंगे। अध्यक्ष एवं अंशकालिक सदस्यों की अन्य निबन्धन एवं शर्तें यथाविनिर्धारित होंगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उप राज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर

डॉ. फिलिप थेंगलीनमंग, विशेष सचिव (डीएससीएसटी)

DEPARTMENT FOR WELFARE OF SC/ST/OBC**NOTIFICATION**

Delhi, the 5th July, 2019

F. No. 28(18)/2017-18/DSCST/Plg/Vol-I/8253-65.—In pursuance of Clause 14 of the notification No. F. 28(93)/91-92/SCST/P&S/109 dated 20th, April, 1993, vide which the Commission for Other Backward Classes of the National Capital Territory of Delhi was constituted by the Lt. Governor of NCT of Delhi, and Cabinet decision No. 2600 dated 17-07-2018, the Government is pleased to regulate the salary and allowances payable to Chairperson and part-time Members of the Commission for Other Backward Classes of the National Capital Territory of Delhi as under wef: 17-07-2018.

“Consolidated salary of the Chairperson shall be Rs.2,00,000/- (Two Lakh only) per. month without allowance and in addition, the Chairperson shall be entitled to a car and house (or HRA as applicable as per rules). The Part-time Members shall be entitled for a monthly amount of Rs.1,00,000/- (one Lakh only) consolidated without allowances . Other terms and conditions of the service of the Chairperson and Part-time Members shall be such as may be prescribed”.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

Dr. PHILIP THANGLIENMANG, Special Secy. (DSCST)